विकास प्राधिकरणों में सेवानिवृत्त कार्मिकों की सेवाएं लेने की तैयारी

राज्य ब्यूरो, देहरादून: उत्तराखंड में विकास प्राधिकरणों को प्रभावी बनाने के दृष्टिगत सरकार ने इनमें रिक्त पदों को भरने के साथ ही कुछ नए पद भी सृजित किए हैं, लेकिन इन्हें भरने में समय लग रहा है। इस परिस्थिति में प्राधिकरणों का कामकाज प्रभावित न हो, इसके लिए राज्य लोक सेवा आयोग से नियुक्तियां और आउटसोर्सिंग से व्यवस्था होने तक प्राधिकरणों के सेवानिवृत्त कार्मिकों की सेवाएं लेने पर भी गंभीरता से विचार चल रहा है। अगले माह तक कुछ सेवानिवृत्त कार्मिकों को विभिन्न प्राधिकरणों में तैनाती दी जा सकती है।

नगरीय क्षेत्रों के साथ ही इनके समान परिस्थितियों वाले क्षेत्रों के नियोजित विकास के दृष्टिगत पूर्व में सभी जिलों में विकास प्राधिकरण गठित किए गए थे। तब इनमें 131 पदों का सृजन किया गया, लेकिन वर्तमान में इनमें नगर नियोजकों के साथ ही तकनीकी रूप से दक्ष कार्मिकों की भारी कमी है। ऐसे में नगरीय क्षेत्रों की महायोजना के कार्यों के पर्यवेक्षण और अनुश्रवण में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है। इस सबको देखते हुए इसी माह की शुरुआत में हुई कैबिनेट की बैठक में प्राधिकरणों में कुल 230 पदों के सृजन पर मुहर लगी थी। इसमें मुख्यालय स्तर पर 124 और जिला स्तर पर 106 पद रखने का निर्णय लिया गया। इस बीच विभिन्न पदों को भरने के दृष्टिगत राज्य लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजे गए, लेकिन इसमें समय लग रहा है। ऐसे में आउटसोर्स अथवा प्रतिनियुक्ति पर भी प्राधिकरणों में तैनाती देने का निर्णय लिया गया था, लेकिन यह प्रक्रिया भी लंबी है।

इन सब परिस्थितियों के चलते प्राधिकरणों का कामकाज प्रभावित न हो और वहां से जनता को बेहतर सेवाएं मिलती रहें, इसे देखते हुए प्राधिकरणों के सेवानिवृत्त कार्मिकों से संपर्क साधा जा रहा है।